भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5314

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

खान प्रहरी योजना

5314. श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खान प्रहरी योजना का उद्देश्य और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश की सभी कोयला खानों में योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार किस प्रकार योजना बना रही है;

(ग) उक्त योजना के तहत कोयला खानों में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीक और उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार इस योजना के माध्यम से कोयला खानों में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार विचार कर रही है; और

(ङ) खान प्रहरी योजना को लागू करने में अब तक उपगत लागत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : 'खनन प्रहरी' एक मोबाइल ऐप है जो आम जनता उपयोग के लिए है ताकि वे अवैध कोयला खनन की घटनाओं, यदि कोई हों, के विरूद्ध अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। यह मोबाइल ऐप कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के साथ मिलकर काम करता है जो कोयला मंत्रालय के निदेश के तहत केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड के परामर्श से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा विकसित एक वेब-जीआईएस आधारित प्रणाली है।

खनन प्रहरी मोबाइल ऐप के साथ सीएमएसएमएस पोर्टल जुलाई 2018 में शुरू किया गया था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अवैध कोयला खनन गतिविधियों की रोकथाम के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह चित्रों और खनन प्रहरी ऐप के जरिए प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अवैध कोयला खनन गतिविधियों की निगरानी करना था।

यदि सीएमएसएमएस पोर्टल पर खनन प्रहरी के माध्यम से कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो सीएमएसएमएस पोर्टल के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के साथ-साथ राज्य सरकारों में संबंधित अधिकारियों/नोडल अधिकारियों को अलर्ट जारी हो जाता है। सीएमएसएमएस पोर्टल पर दर्ज वैध सही शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने से पहले इन शिकायतों की वास्तविकता के आधार पर इनका वैध होना आवश्यक है।

(ख) : खनन प्रहरी मोबाइल ऐप के साथ सीएमएसएमएस वेब जीआईएस पोर्टल जुलाई, 2018 में इसे शुरू किए जाने के बाद से ही लगातार परिचालन में है। आज की तारीख तक खनन प्रहरी ऐप के माध्यम से 473 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन मामलों में वास्तविक सत्यापन किया गया, जिनमें से 77 शिकायतें आधार सत्यापन के बाद सही पाई गईं थी, जिन पर उपयुक्त कार्रवाई की गई थी/कदम उठाए गए थे।

(ग) : सीएमएसएमएस और खनन प्रहरी से संबंधित सूचना पब्लिक डोमेन में कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की वेबसाइटों तथा एनसीओजी वेबसाइट पर भी डाली जाती है। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप डाउनलोड और उपयोग करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है।

(घ) : खनन प्रहरी ऐप के दायरे में परिकल्पित नहीं है।

(ड.) : मोबाइल एप्लिकेशन "खनन प्रहरी" और वेब एप्लिकेशन 'कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस)' भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, (बीआईएसएजी), गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया था। इन एप्लीकेशन को बीआईएसएजी द्वारा निःशुल्क विकसित किया गया था।

****

अनुबंध - I

फरवरी 2023 तक सीएमएसएमएस पोर्टल पर खनन प्रहरी ऐप के माध्यम से दर्ज अवैध कोयला खनन शिकायतों की वर्ष-वार स्थिति				
कंपनी/राज्य	**सत्यापित झूठी शिकायतें**	**सत्यापित सच शिकायतें**	**शिकायतें जिनका सत्यापन अभी किया जाना है**	**कुल जोड़**
2018				
सीआईएल (सहायक कंपनी)				
बीसीसीएल	6	2		8
सीसीएल	1	3		4
ईसीएल	21	4		25
एनसीएल	3			3
एसईसीएल	1			1
गैर सीआईएल (राज्य)				
असम	1	2		3
छत्तीसगढ़	6			6
झारखंड			2	2
मध्य प्रदेश	4		1	5
महाराष्ट्र			1	1
ओडिशा	1			1
पश्चिम बंगाल	1		8	9
कुल (2018)	**45**	**11**	**12**	**68**
2019				
सीआईएल (सहायक कंपनी)				
बीसीसीएल	12			12
सीसीएल	1	5		6
ईसीएल	86	32		118
एमसीएल	1			1
एनसीएल	3			3
एसईसीएल	11			11
डब्ल्यूसीएल	2			2

गैर सीआईएल (राज्य)				
असम		1		1
छतीसगढ़			2	2
झारखंड	1		8	9
मध्य प्रदेश			24	24
महाराष्ट्र			7	7
ओडिशा	1		3	4
पश्चिम बंगाल			25	25
कुल (2019)	**118**	**38**	**69**	**225**
2020				
सीआईएल (सहायक कंपनी)				
बीसीसीएल	3			3
सीसीएल		2		2
ईसीएल	79	22		101

अनुबंध - I

कंपनी/राज्य	सत्यापित झूठी शिकायतें	सत्यापित सच शिकायतें	शिकायतें जिनका सत्यापन अभी किया जाना है	कुल जोड़
एसईसीएल	1			1
गैर सीआईएल (राज्य)				
छत्तीसगढ़			2	2
झारखंड			3	3
मध्य प्रदेश			5	5
महाराष्ट्र			1	1
पश्चिम बंगाल			23	23
कुल (2020)	**83**	**24**	**34**	**141**
2021				
सीआईएल (सहायक कंपनी)				
बीसीसीएल	2			2
सीसीएल		4		4
ईसीएल	1			1
गैर सीआईएल (राज्य)				
छत्तीसगढ़			3	3
झारखंड			1	1
महाराष्ट्र			1	1
कुल (2021)	**3**	**4**	**5**	**12**
2022				
सीआईएल (सहायक कंपनी)				
बीसीसीएल	1			1
गैर सीआईएल (राज्य)				
छत्तीसगढ़			1	1
कुल (2022)	**1**		**1**	**2**
2023				
सीआईएल (सहायक कंपनी)				
बीसीसीएल			23	23
एनसीएल			2	2
कुल (2023)			**25**	**25**
कुल जोड़	**250**	**77**	**146**	**473**